



सुशासन

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल

School of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal

छटवा वार्षिक प्रतिवेदन
(01 अप्रैल 2012 – 31 मार्च 2013)

Sixth Annual Report
(1st April 2012 – 31st March 2013)

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल

(मध्यप्रदेश शासन की स्वशासी संस्था)

सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल-462003

फोन नं – 0755-2777316, 2777318, 2770538

वेबसाइट: www.sushasanmp.in, ई-मेल: sushasank@gmail.com

विषय-सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	अध्याय- एक स्कूल संबंधी सामान्य जानकारी	
	1.1 स्कूल के उद्देश्य	1
	1.2 स्कूल की अवधारणा (Vision)	2
	1.3 स्कूल के ध्येय (Mission)	2
	1.4 स्कूल की कार्यप्रणाली	2
	1.5 स्कूल के कार्य स्तंभ	3
	1.6 स्कूल के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ	3
	1.7 स्कूल के संकल्प	3
2	अध्याय- दो वर्ष 2012-13 की मुख्य गतिविधियाँ	
	2.1 स्कूल की नवीन बेवसाईट का निर्माण	4
	2.2 इन्टर्नशिप कार्यक्रम	4
	2.3 "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010" अन्तर्गत 200 मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	5
	2.4 लोक सेवा केन्द्रों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	6
	2.5 एकीकृत परिपेक्ष्य योजना 2012-17 एवं वार्षिक कार्ययोजना बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्कूल का तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन	6
	2.6 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु आवेदनों का क्षेत्र निरीक्षण	6
	2.7 जिला आपदा प्रबंधन एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण	7
	2.8 "आइडियाज़ फॉर सीएम" बेवसाईट	7
	2.9 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "लैल अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेष परियोजना की मॉनिटरिंग एवं समन्वय का कार्य	8
	2.10 नवाचारों के अभिलेखीकरण एवं प्रचार-प्रसार	9
3	अध्याय- तीन सेमीनार/ कार्यशालाएँ	
	3.1 "Ethical Governance through Inner Governance" विषय पर कार्यशाला का आयोजन	10
4	अध्याय- चार वित्तीय प्रतिवेदन	11

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5	अध्याय— पाँच नवीन नियुक्तियों 5.1 स्कूल में सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन	12
6	अध्याय – छः कोर स्टॉफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग	13
7	अध्याय— सात स्कूल की गवर्निंग बॉडी एवं एकजीक्यूटिव बॉडी 7.1 स्कूल की गवर्निंग बॉडी 7.2 स्कूल की एकजिक्यूटिव बॉडी	14 15
8	परिशिष्ट-1 इन्टर्नशिप कार्यक्रम 2012-13	16-18

अध्याय- एक स्कूल संबंधी सामान्य जानकारी

1.1 स्कूल के उद्देश्य-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-8/2007/1/9 भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2007 द्वारा सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की भोपाल में स्थापना की गई है। सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय (Global-Local) परिपेक्ष्य में "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करना। शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना।
- सुशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, कार्य योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करना।
- उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा ई-प्रशासन के कार्यक्रमों का संकलन कर उनका विस्तारण करना।
- प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं उनके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन संबंधी परामर्श देना।
- ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना, जिनमें परिवर्तन एवं सुधार से प्रशासनिक परिणामों तथा उपलब्धियों पर अधिकतम सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।
- प्रशासन को जन-केन्द्रित बनाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा संबद्ध हितग्राहियों के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- स्थानीय निकाओं, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिये कार्यक्रमों की संरचना एवं संचालन, एक्शन रिसर्च एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के लिये तकनीकी परामर्श एवं सेवायें उपलब्ध कराना।

1.2 स्कूल की अवधारणा (Vision)–

“सुशासन जो सबको समान अवसर प्रदान करे एवं जिसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना हो।”

(“Equal opportunity to all through Good Governance geared to improve the quality of lives of our People”).

1.3 स्कूल के ध्येय (Mission) –

“Knowledge Resource Hub और Repository के निर्माण एवं अन्य माध्यमों द्वारा सुशासन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के विकास का प्रयास, सुनिश्चित करना, जिससे शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित तथा जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाया जा सके” ।

(“Develop Knowledge Resource Hub and Repository and other strategies, to motivate and encourage strengthening of Good Governance which is more transparent, participative, accountable and focused on improving the quality of lives of our people”).

1.4 स्कूल की कार्यप्रणाली –

संचालक (सुशासन), संचालक (नीति विश्लेषण) तथा संचालक (ज्ञान प्रबन्धन), कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना अधिकारी/अनुसंधान संयुक्त/शोधकर्ता (Programme Coordinators/Project Officers/ Research Associates/ Research Fellows), तथा प्रशासनिक स्टाफ के सहयोग से स्कूल का कार्य संपादित होगा। परियोजनाओं से संबंधित विशिष्ट परामर्शदायी विशेषज्ञ/सलाहकार (Distinguished Specialists / Advisors), विशिष्ट फेलो/कन्सलटेंट (Distinguished Fellows/Consultants) संस्थागत/एक्सचेंज कार्यक्रम फेलों (Institutional Fellows, Exchange Programme Fellows) तथा कार्यक्षेत्र अनुभवी विशेषज्ञ (Experts with Field Experience) से भी सहयोग लिया जायेगा।

1.5 स्कूल के कार्य स्तंभ –

- शोध, नीति विश्लेषण एवं विकास
- सुशासन के लिए क्षमता विकास को प्रोत्साहन
- प्रबंधन तकनीकियों का सुशासन के लिये उपयोग

1.6 स्कूल के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ –

- शासन में नवाचार
- सेवाओं में सुधार और *grassroots* तक विस्तार
- शासन का विकेन्द्रीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास
- शासन में आम समाज की साझेदारी
- ई-शासन
- सुशासन के लिए *knowledge hub* और *repository* का निर्माण
- समान उद्देश्यों वाली अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय की स्थापना
- सुशासन को प्रोत्साहन

1.7 स्कूल के संकल्प –

- सुशासन संबंधी नीतियों के पालन में शासन को सहयोग प्रदान करने के लिए स्कूल संकल्पित है।
- स्कूल विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर सुशासन स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा।
- आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयासों में स्कूल सहयोगी होगा।

अध्याय – दो वर्ष 2012-13 की मुख्य गतिविधियाँ

2.1 स्कूल की नवीन वेबसाईट का निर्माण—

नवीनतम तकनीक (PHP, Zhoomla) का उपयोग करते हुए स्कूल की नवीन वेबसाईट का निर्माण किया गया तथा स्कूल द्वारा समय-समय पर संचालित गतिविधियों की अद्यतन जानकारी को वेबसाईट पर निरंतर अद्यतन किया गया है।

2.2 इन्टर्नशिप कार्यक्रम—

शासन तंत्र से आई.आई.एम, आई.आई.टी. जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एवं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जैसे राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों के प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों को जोड़ने हेतु स्कूल द्वारा वर्ष 2009 से इंटर्नशिप व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष इन्टर्नस् का चयन उपरोक्त संस्थानों के एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में से किया जाता है। चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित होती है—

- इन्टर्नशिप व्यवस्था की जानकारी प्रतिवर्ष माह सितम्बर में सभी विभागों को प्रेषित करते हुए आगामी वर्ष में अप्रैल से जुलाई के अंतराल में अध्ययन हेतु योजनाओं संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं।
- स्कूल की वेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर इच्छुक इंटर्न द्वारा अपनी संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन स्कूल को प्रेषित किये जाते हैं।
- इंटर्न की योग्यता और रुचि को ध्यान में रखते हुये संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी तथा स्कूल के कोर स्टाफ द्वारा प्राथमिक रूप से चुने गये आवेदकों का वीडियो-कांफ्रेंस/टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात् चयन किया जाता है।
- शासकीय विभागों द्वारा चिन्हित नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के अध्ययन के लिये स्कूल के कोर स्टाफ द्वारा समन्वय का कार्य किया जाता है।

- प्रत्येक इंटर्न द्वारा अध्ययन उपरांत अपने सुझाव एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2012-13 हेतु कुल 53 इंटर्नस् का चयन किया गया था। चयनित इंटर्नस् आई.आई.एम-इंदौर, आई.आई.टी.-कानपुर, जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट-भुवनेश्वर, आई.आई.टी.-मद्रास, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान-भोपाल, आई.आई.टी.-गोहाटी एवं आई.आई.टी.-रूड़की से थे। इनमें से 50 इंटर्नस् द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन योजना बनाने का कार्य किया गया है तथा 03 इंटर्नस् द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित योजनाओं पर अध्ययन कार्य किया गया है। चयनित इंटर्नस् एवं उनके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट का विवरण **परिशिष्ट-1** में उपलब्ध है।

वर्ष 2013-14 के लिए मैं इन्टर्नशिप कार्यक्रम अंतर्गत देश की विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थाओं से 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 22 आवेदकों का चयन किया गया है। चयनित इंटर्नस् द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, म.प्र. विद्युत नियमक आयोग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित विषयों पर अध्ययन कार्य किया जाएगा।

2.3 “मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010” अन्तर्गत 200 मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन-

“मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010” अंतर्गत प्रदेश के 200 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिनांक 23.07.2012 से 24.08.2012 तक 04 बैच में भोपाल में आयोजित किया गया। प्रत्येक बैच का प्रशिक्षण 04 दिवस का था, जिसमें प्रथम 02 दिवस लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम पर चर्चा एवं शेष 02 दिवस में साफ्टवेयर आधारित प्रशिक्षण दिया गया।

2.4 लोक सेवा केन्द्रों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण-

प्रदेश में पी.पी.पी. मोड में खोले जा रहे सभी लोक सेवा केन्द्रों के एक-एक प्रतिनिधि (कुल 350 प्रतिनिधियों) का दो दिवसीय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा भोपाल में दिनांक 27.08.2012 से 12.09.2012 तक 07 समूहों में आयोजित किया गया। प्रत्येक समूह का प्रशिक्षण 02 दिवस का एवं प्रत्येक समूह में प्रतिभागियों की संख्या लगभग 50 थी। इस प्रशिक्षण में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम एवं आवेदनों की ऑनलाईन प्रोसेसिंग के लिए बनाये गये साफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।

2.5 एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना 2012-17 एवं वार्षिक कार्ययोजना बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन -

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए तकनीकी सहायता संस्थाओं के चयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव मांगे गये थे। मध्यप्रदेश के 06 जिलों (अनूपपुर, दमोह, डिण्डोरी, कटनी, सिवनी एवं शहडोल) की एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक प्लान बनाने हेतु स्कूल के प्रस्ताव को चुनते हुए तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन किया गया है।

स्कूल द्वारा एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त सभी 06 जिलों के सभी विकासखण्डों के पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से योजना तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई एवं संबंधित विकासखण्ड की प्रमुख प्राथमिकतायें चिन्हित करते हुए उपरोक्त सभी जिलों की वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना तैयार कर जिला योजना समिति के अनुमोदन हेतु संबंधित जिला पंचायतों को प्रेषित की जा चुकी हैं।

2.6 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु आवेदनों का क्षेत्र निरीक्षण-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को सर्वोत्कृष्ट, स्वप्रेरक एवं नवाचार कार्य के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिये जाते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2011 के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये प्राप्त आवेदनों में से प्रारंभिक रूप से चयनित 19 आवेदनों के क्षेत्र सत्यापन का कार्य सुशासन एवं नीति

विश्लेषण स्कूल को सौपा गया था। स्कूल द्वारा यह कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण कर प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौपा गया।

2.7 जिला आपदा प्रबंधन एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण-

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का कार्य स्कूल को सौपा गया है। इस कार्य हेतु गृह विभाग द्वारा स्कूल के प्रस्ताव अनुसार राशि रू. 33.39 लाख की स्वीकृति दी गई है। स्कूल द्वारा यह कार्य प्रत्येक जिले के लिए एक इंटरन, इस प्रकार कुल 50 इंटरनस के माध्यम से किया जाएगा। चयनित 50 इंटरनस आई.आई.टी. मद्रास, आई.आई.एफ.एम, भोपाल, आई.आई.टी. कानपुर, जेवियर इस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट-भुवनेश्वर आई.आई.टी. गोहाटी तथा आई.आई.टी. रूढ़की के एम.बी.ए. के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। इंटरनस को मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल द्वारा सीडस् टेक्निकल सर्विसेस, नई दिल्ली को कन्सल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया। स्कूल द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजना एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजना निर्माण का कार्य पूर्ण कर माह अक्टूबर 2012 में गृह विभाग एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित की जा चुकी है।

2.8 "आइडियाज़ फॉर सीएम" वेबसाइट-

आम जनता को सुशासन एवं विकास की वैचारिक प्रक्रिया से व्यापक रूप से जोड़ने एवं इनके अनुभव और ज्ञान के अपार भण्डार का लाभ प्रदेश के विकास की प्रक्रिया में लेने के लिए स्कूल द्वारा "आइडियाज़ फॉर सीएम" वेबसाइट का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 19.01.2009 को किया गया था। इस वेबसाइट के माध्यम से विश्व के किसी भी हिस्से से सुशासन एवं विकास के संबंध में सुझाव प्रेषित किये जा सकते हैं।

प्राप्त आइडियाज के विश्लेषण एवं अनुश्रवण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गई है। नागरिकों द्वारा किसी आइडिया को प्रेषित करते ही उन्हें ई-मेल के माध्यम से आइडिया प्राप्त होने की सूचना दी जाती है। आइडिया की प्रारंभिक छानबीन के उपरांत यदि आइडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उस आइडिया को पंजीकृत कर संबंधित विभाग को अभिमत हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। साथ ही सुझावकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उसके सुझाव के पंजीयन की सूचना

देते हुए एक आई-डी एवं पासवर्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से सुझावकर्ता उसके आईडिया पर समय-समय पर की गई कार्यवाही की स्थिति जान सकता है। यदि प्रारंभिक छानबीन के उपरांत आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में भी सुझावकर्ता को ई-मेल के माध्यम से सूचना दी जाती है। पंजीकृत आईडिया पर विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरांत पुनः आईडिया का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरांत आईडिया के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के संबंध में भी सुझावकर्ता को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

इस वेबसाइट को www.ideasforcm.in पर देखा जा सकता है। वर्ष 2012-13 के दौरान इस वेबसाइट के माध्यम से 891 आईडियाज़ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रारंभिकतौर पर चयनित 52 आईडिया संबंधित विभागों के अभिमत हेतु प्रेषित किए गए हैं।

2.9 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SGSY अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेष परियोजना की मॉनिटरिंग एवं समन्वय का कार्य—

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस.जी.एस.वाय. अंतर्गत मध्यप्रदेश के 12 पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे दस हजार बेरोजगार युवक/युवतियों को सघन प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेष परियोजना स्वीकृत की गई है। योजना की कुल लागत राशि रु. 1496.00 लाख है, जिसमें केन्द्रांश राशि रु. 1122.00 लाख एवं राज्यांश राशि रु. 374.00 लाख है। परियोजना की अवधि दो वर्ष है एवं परियोजना अवधि में 12 जिलों के 10,000 युवाओं/युवतियों को 9 ट्रेड में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाना है। योजना का क्रियान्वयन "क्रिस्प" (Centre for Research and Industrial Staff Performance) द्वारा किया जायेगा। परियोजना अंतर्गत 09 ट्रेड— 1. रेडीमेड गारमेंट मेकिंग, 2. सेल्स एवं मार्केटिंग, 3. सिक्वोरिटी सर्विस, 4. कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयर एवं

मेन्टेनेन्स, 5. बेसिक इलेक्ट्रिशियन, 6. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 7. मशीन मेकेनिक, 8. आटोमेशन इन्जीनीयरिंग, 9. हेण्ड्रीक्राफ्ट, में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्रियान्वन संस्था द्वारा मार्च 2013 तक योजना अर्न्तगत 9658 हितग्राहियों का चयन कर 8037 हितग्राहियों को प्रशिक्षण तथा 5864 हितग्राहियों को प्रशिक्षण उपरान्त उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। स्कूल द्वारा परियोजना का समय-समय पर अनुश्रवण एवं समन्वय करते हुये प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

2.10 नवाचारों के अभिलेखीकरण एवं प्रचार-प्रसार –

नवाचारों के अभिलेखीकरण एवं प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत स्कूल द्वारा वर्ष 2012-13 में निम्न 2 बेस्ट प्रेक्टिस का अभिलेखीकरण एवं प्रकाशन तथा एनआईटीटीटीआर, भोपाल के सहयोग से वीडियो फिल्म तैयार कर दिसंबर 2012 में भारत सरकार को प्रेषित की गई।

- "Implementation of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights)Act, 2006 in Madhya Pradesh"
- "Removal of Encroachment Structures of Different Religions Maintaining Communal Harmony"

अध्याय – तीन सेमीनार / कार्यशालाएँ

3.1 "Ethical Governance through Inner Governance" विषय पर कार्यशाला का आयोजन—

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल का एक मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार को प्रोत्साहित करना भी है। इसी कड़ी में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा इनीशिएटिव ऑफ चेंज (IofC) संस्था के संयुक्त तत्वाधान में "Ethical Governance through Inner Governance" विषय पर दिनांक 16, 17 एवं 18 मार्च 2013 को तीन एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन इण्डिया पर्यावरण परिसर, भोपाल में किया गया। इन तीन कार्यशालाओं में से दो कार्यशालाएं शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिये एवं एक कार्यशाला स्वयंसेवी संगठनों एवं जन-सामान्य हेतु आयोजित की गई थी। इन तीन कार्यशालाओं में कुल 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सहभागियों को उनकी सकारात्मक सोच और अच्छाइयों से परिचित कराने का प्रयास करना था ताकि इस सोच का प्रभाव उनके कार्य-स्थल, कार्यशैली और दैनिक दिनचर्या में परिलक्षित हो सके एवं वे अपने कार्यस्थल, समाज एवं परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार तथा प्रभावशाली हो सकें।

—00—

अध्याय – चार
वित्तीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13 में स्कूल के लिए रुपये 450.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित था-

भाग संख्या- 01

मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालयीन सामान्य सेवायें

राज्य आयोग (सामान्य)- 101

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना (5163) -

मद		राशि (लाख में)
001 - अद्योसंरचना अनुदान	-	000
002 - संधारण अनुदान	-	450
योग	-	450

उपरोक्तानुसार प्रावधानित बजट से स्कूल द्वारा वर्ष 2012-13 में रुपये 225 लाख की राशि आहरित की गई एवं शेष राशि रुपये 225 लाख समर्पित की गई ।

अध्याय – पाँच नवीन नियुक्तियों

5.1 स्कूल में सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन—

स्कूल में सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन हेतु आवेदन जनवरी 2013 में आमंत्रित किए गए। आवेदनो की छटनी का कार्य स्कूल द्वारा किया गया। छटनी उपरान्त 58 उम्मीदवारो को चयन प्रक्रिया अंतर्गत लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कर के लिए आमंत्रित किया गया। उक्त पदो हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारो का चयन फरवरी 2013 में किया गया:—

स. क्र.	चयनित उम्मीदवारों का नाम	पदनाम
1	श्री कैलाश डावर	सहायक ग्रेड -2
2	श्री जितेन्द्र मालवीय	सहायक ग्रेड -3
3	श्री रविन्द्र चौहान	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

—00—

अध्याय – छः
कोर स्टॉफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग

6.1 श्री अखिलेश अर्गल, संचालक (सुशासन) आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में "सूचना का अधिकार विषय" पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के रूप में नियमित रूप से अपनी सेवाएँ दी हैं।

—00—

अध्याय – सात
स्कूल की गवर्निंग बॉडी एवं एकजीक्यूटिव बॉडी

7.1 स्कूल की गवर्निंग बॉडी –

स्कूल की गवर्निंग बॉडी निम्नानुसार है:-

क्र.	सदस्य नाम/पद	धारित पद
1.	माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्रीजी, वित्त	सदस्य
3.	माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
4.	माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
5.	माननीय मंत्रीजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
6.	माननीय मंत्रीजी, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण	सदस्य
7.	माननीय मंत्रीजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय	सदस्य
8.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
9.	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
12.	संचालक, भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	सदस्य
13.	राज्य शासन द्वारा नामांकित प्रशासन एवं प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े अधिकतम पाँच सदस्य	सदस्य
14.	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

सरल क्रमांक 13 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-8/2007/1/9 दिनांक 22 अप्रैल 2008 द्वारा नामांकित पाँच सदस्यों का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। नये सदस्यों का नामांकन राज्य शासन द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

7.2 स्कूल की एक्जिक्यूटिव बॉडी –

स्कूल की एक्जिक्यूटिव बॉडी निम्नानुसार है:-

क्र.	सदस्य नाम/पद	धारित पद
1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
8.	शासन द्वारा नामांकित अधिकतम पांच अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

सरल क्रमांक 8 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-8/2007/1/9 दिनांक 22 अप्रैल 2008 द्वारा नामांकित पाँच सदस्यों का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। नये सदस्यों का नामांकन राज्य शासन द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

इन्टर्नशिप कार्यक्रम 2012-13

A. Intern attached with State Disaster Management Authority (SDMA): Prepration of District Disaster Management Plan.

S.No.	Name of Intern	Name of Institute and Course	Alloted District
1	Mr. Anuj Tiwari	IIT-Madras, MBA	Panna
2	Mr. Anil Kumar	IIT Madras, MBA	Balaghat
3	Mr. Chirag Jain	IIT Madras, MBA	Seoni
4	Ms. Rakhi S Kumar	IIT- Madras, Integrated MA	Singroli
5	Mr. Sumedh Bansod	IIFM, PGDFM	Badwani
6	Ms. Diksha Yashwant Lokhande	IIFM, PGDFM	Betul
7	Mr. Rohit Waman Gharde	IIFM, PFM	Rajgarh
8	Mr. Kumar Vibhanshu	IIFM, PGDFM	Narsinghpur
9	Mr. Rishabh Gangwar	IIFM, Forest Management	Harda
10	Mr. Sanchit Arora	IIFM, PGDFM	Mandsaur
11	Dr. Ankaj Sharma	IIFM, PGDFM	Khandwa
12	Mr. Advait U. Mohole	IIFM, PGDFM	Ratlam
13	Miss Ankita Yadav	IIFM, PGDFM	Ujjain
14	Mr. Ankit Pawar	IIFM, PGDFM	Katni
15	Mr. Nimesh Soni	IIFM, PGDFM	Reeva
16	Ms. Ankita Singh	IIFM, PGDFM	Gwalior
17	Mr. Deepanjan Kundu	IIFM, PGDFM	Guna
18	Mr. Amit Kumar	IIFM, PGDFM	Dhar
19	Mr. Mayank Singh	IIT KANPUR Course: MBA	Shahdol
20	Mr. Ankit Narula	IIT KANPUR Course: MBA	Neemach
21	Mr. Pankaj Kumar Rai	IIT-Kanpur Course: MBA	Satna

22	Mr. Nishant Maheshwari	IIT KANPUR Course: MBA	Sidhi
23	Ms. Taruna	IIT KANPUR Course: MBA	Sehore
24	Shri Deepak Gaur	MBA, IIT-Kanpur	Chatarpur
25	Mr. Ummed Singhoriya	IIT-Kanpur Course: MBA	Teekamgarh
26	Mr. Swapnil Jangale	IIT-Kanpur Course: MBA	Sajapur
27	Mr. Bhushan Patne	MBA, IIT -Kanpur	Seopur
28	Mr. Ram Prasad V	MBA, IIT -Kanpur	Jhabua
29	Mr. Sandeep Kumar Chaurasia	MA, IIT Guwahati	Sagar
30	Mr. Saket Vardhan	XIMB, PGDM-RM	Jabalpur
31	Ms. Sheena Kapoor	XIMB, PGDM-RM	Hoshangabad
32	Mr. Chandan Raut	XIMB, PGDM-RM	Khargon
33	Ms. Priyanka Pokhriyal	XIMB, PGDM-RM	Bhopal
34	Mr. Vishal Jansuhia	XIMB, PGDM-RM	Datia
35	Mr. Himanshu Rai	XIMB, PGDM-RM	Bhind
36	Mr. Binayak Acharya	XIMB, PGDM-RM	Shivpuri
37	Ms. Aparna Gautam	XIMB, PGDM-RM	Raisen
38	Mr. Arpit Asthana	XIMB, PGDM-RM	Burhanpur
39	Ms. Madhuri Swamy	XIMB, PGDM-RM	Devas
40	MD. NAFIS HAIDER	XIMB, PGDM-RM	Ashoknagar
41	Ms. Saumya Srivastava	XIMB, PGDM-RM	Chhindwara
42	Mr. Utkarsh Tripathi	XIMB, PGDM-RM	Damoh
43	Ms. Vrittika Srivastava	XIMB, PGDM-RM	Vidisha
44	Mr. Yogesh Kumar Joshi	XIMB, PGDM-RM	Anuppur
45	Mr. Divya Vikas sharma	XIMB, PGDM-RM	Umariya
46	Ms. Pinky Gregory	XIMB, PGDM-RM	Indore
47	Mr. Mayank Saxena	MBA, IIT-Roorkee	Alirajpur
48	Mr. Amit Mahajan	MBA, IIT-Roorkee	Dindori
49	Mr. Sayantan Chattopadhyay	MBA, IIT-Roorkee	Murena
50	Mr. Shiva Prasad Rao	MBA, IIT-Roorkee	Mandla

B. Interns attached with other departments:-

S.No.	Name of Intern	Name of Institute	Department Assigned	Study Topic
1	Shri Sandip S.M.	IIM-Indore	Panchayat and Rural Development	Study of Rural Connectivity through Convergence of MGNREGA and CMGSY
2	Shri Rohit Basauri	XIM-Bhubaneswar	Panchayat and Rural Development	Impact Assessment of MIS used in MGNREGA and new innovations through IT
3	Shri Nitin Bhardwaj	IIT-Kanpur	M.P. Biotechnology Council	Status of Bio Technology in Madhay Pradesh

—00—